सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-33 अंक-21 | 7 से 21 नवम्बर, 2018 | मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

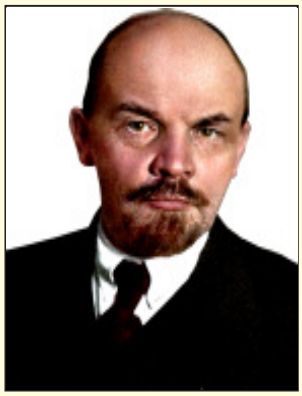

महान नवम्बर क्रान्ति जिन्दाबाद

"आप तभी कम्युनिस्ट बन सकेंगे जब आप अपने जेहन को मानव-जाति द्वारा अर्जित सारी ज्ञान-सम्पदा से सम्पन्न कर लेंगे।"– लेनिन (युवक संघों के कार्यभार)

"मार्क्सवाद इस बात का द्योतक है कि मानव-ज्ञान की निधि से कम्युनिज्म का किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ।" (वही)

"अगर मैं समझूं कि मेरी जानकारी बहुत सीमित है, तो मैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा; लेकिन अगर कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट होने का दावा करता है और कहता है कि उसे अब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, तो इससे वह कम्युनिस्ट सरीखा आदमी कभी नहीं बनेगा।"(वही)

. "जनवादी जनतंत्र ही पूंजीवाद के लिए सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक खोल है, और इसलिए, इस सर्वश्रेष्ठ खोल पर एक बार अधिकार कर लेने के बाद पूंजी अपनी ताकत को इतनी मजबूती से, इतनी दृढ़ता से जमा लेती है कि फिर उस पूंजीवादी जनवादी जनतंत्र से व्यक्तियों, संस्थाओं या पार्टियों की कोई भी अदला-बदली उस ताकत को नहीं हिला सकती। हर कुछ वर्षों के बाद यह तै कर देना कि सत्तारूढ़ वर्ग का कौन सदस्य संसद में जाकर जनता का दमन और उत्पीड़न करेगा यही पूंजीवादी संसदवाद का सच्चा सार है।" – लेनिन (राज्य और क्रांति)

"हमने असामान्य रूप से कठिन परिस्थितियों में हमारी क्रांति शुरू की थी, जैसे कि दुनिया में श्रमिकों की किसी भी अन्य क्रांति को सामना करना पड़ेगा। .... हमें दुनिया में सर्वहारा और समाजवादी सेना की इकाइयों में से एक, अगुआ दस्तों में से एक होना चाहिए।" – लेनिन (क्रांति की सालगिरह पर भाषण, 1920)

आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव

जन आंदोलन की राजनीति को मजबूत करें, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) को अपना समर्थन दें

पिछले तीन कार्यकालों से बीजेपी द्वारा शासित राज्य मध्य प्रदेश में 28 नवंबर 2018 को मतदान होगा। बीजेपी के बड़बोले मुख्यमंत्री का दावा है कि उन्होंने बीमार राज्य का विकास किया है। लेकिन तथ्य इसके उलट गवाही देते हैं, यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट और सरकारी आंकड़े भी उनके दावे की पोल खोलते हैं। जहां लोग गरीबी, निरक्षरता, असुरक्षा, आपराधिक गतिविधियों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और माफियागिरी के तहत पिस रहे हैं, वहीं पूंजीवादी-कॉर्पोरेट-बड़े कारोबारियों ने इस खुशहाली की सारी फसल काट ली है। जहां देश में मुद्रास्फीति की आधिकारिक दर 107% है, वहीं मध्य प्रदेश में यह लगभग दोगुनी 197% है। मध्य प्रदेश डीजल, पेट्रोल और एलपीजी पर राज्य कर की मार मारने में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। भयंकर भुखमरी, कुपोषण, महिलाओं व बच्चियों पर अपराधों, महंगाई, बेरोजगारी, स्कूलों की बदहाली, खस्ताहाल अस्पतालों, बिजली के अनाप-शनाप बिलों की मार झेलते आम आदमी को फिर एक बार सुनहरे भविष्य का स्वप्न दिखाया जाएगा। तमाम प्रचार तंत्रों के माध्यम से उसे तथाकथित बदलाव की उम्मीद बंधा कर, इस पूंजीवादी व्यवस्था की 70 वर्षों की विफलता को ढकने का प्रयास किया जाएगा। पूंजीपति वर्ग की सबसे वफादार पार्टियाँ कांग्रेस व भाजपा दोनों में सत्ता में आने की होड़ मची हुई है। दोनों ही पार्टियाँ के नेतागण यात्राएं, जलसा-जुलूस करके यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मानो वे ही आम जनता के सच्चे हितैषी हैं। सच्चाई यह है कि पिछले 15 वर्षों में भाजपा ने उन्हीं जनविरोधी नीतियों को और भी तेजी से आगे बढ़ाया है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस-नीत सरकार ने शुरू की थी। जनता की बदहाली के लिये ये दोनों पार्टियाँ समान रूप से जिम्मेदार हैं।

ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनाव सामने हैं। चुनावों की घोषणा होते ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के गठन से अब तक 14 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इनमें से कोई न कोई पार्टी तो जीती है। पर आम जनता की आज तक भी लगातार हार होती आई है। साल दर साल हालात और भी ज्यादा खराब हुए हैं। इसीलिये एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) आपसे आग्रह करती है कि इन चुनावों में बगैर किसी पूर्वाग्रह के एक सचेत नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आज मध्य प्रदेश में लोगों की बदहाली हृदय विदारक है। उनमें से कुछ पहलुओं पर हम यहां चर्चा करना चाहेंगे।

गरीबी, भुखमरी, महंगाई, कुपोषण में मध्यप्रदेश सबसे आगे

मध्य प्रदेश में गरीबी, कुपोषण और भुखमरी के आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में रोज 92 बच्चे कुपोषण के कारण दम तोड़ देते हैं। वर्ष 2016-2017 इन दो वर्षों में 57 हजार बच्चे भूख -कुपोषण से मारे गये। कुपोषण के मामले में हमारा प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में सितम्बर 2016 में जब 116 बच्चों की कुपोषण से मौत हुई, तब इसकी तुलना अफ्रीका के घोर गरीब देश इथोपिया से कर इस जिले को भारत का इथोपिया कहा गया। भुखमरी के मामले में भी प्रदेश नम्बर एक पर है। हैरत की बात है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में पिछले दो वर्षों में 157 लाख टन अनाज सरकारी गोदामों में सड़ गया। यही है मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का सुशासन!!

वहीं साढ़े सात करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसी विकट स्थिति में प्रदेश की जनता भंयकर महंगाई की मार झेल रही है। रोजमर्रा की जरूरत के सामान महंगे से महंगे होने के कारण आम जनता परेशान है ।आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है, जहां रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के दाम बाकी वस्तुओं की तुलना में ज्यादा बढ़े हैं। जहां पूरे देश में महंगाई दर 107 फीसदी है ,वहीं मध्य प्रदेश में ये दर 197 फीसदी तक बढ़ी है।(दैनिक भास्कर 18 जून 2018)

लगातार पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ने से चारों तरफ हाहाकार है। पेट्रोल-डीजल को सरकार ने जब से नियंत्रण मुक्त किया है, तब से प्रतिदिन मनमाने ढंग से इसके दाम बढ़ रहे हैं। अब दाम बढ़ने पर सरकार कह रही है कि इसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है। पर सवाल है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों पर नियंत्रण को अपने हाथों से जाने किसने दिया ? अब सरकार रसोई गैस को

(शेष पृष्ठ 2 पर)

हरियाणा रोड़वेज के निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरे वाम दलों के कार्यकर्ता

रोहतक : 29 अक्तूबर को चार वामपंथी पार्टियों सीपीआई(एम) के कॉ. सुरेन्द्र सिंह, सीपीआई के कॉ. दरियाव सिंह कश्यप, एसयूसीआई (सी) के कॉ. सत्यवान और सीपीआई (एम-एल) के कॉ. प्रेम सिंह गहलावत ने प्रैस को जारी संयुक्त बयान में कहा : रोड़वेज कर्मचारियों की हड़ताल प्रदेश की भाजपा सरकार की हठधर्मिता की वजह से जारी है। कर्मचारियों पर चलाए जा रहे भीषण दमनचक्र और यात्रियों की जान जोखिम में डालकर जिस तरह नौसिखिये लोगों से बसें चलवाई जा रही है वह घोर निंदनीय है।

वामपंथी नेताओं ने बताया कि 31 अक्तूबर को चारों वामपंथी पार्टियाँ सरकार की रोड़वेज के निजीकरण की नीति के खिलाफ विरोध दिवस मनाएंगी और प्रदेशभर में रोड़वेज कर्मचारियों के समर्थन में रोष प्रदर्शन करेंगी। वामपंथी नेताओं ने कहा कि प्रदेश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने रोड़वेज कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया है। परंतु जिस प्रकार हड़ताल तोड़ने के लिए सरकार द्वारा कर्मचारियों पर दमनचक्र चलाया जा रहा है और जनता को भारी असुविधा

(शेष पृष्ठ 5 पर)

रेवाड़ी (बायें) व भिवानी (दायें) : हरियाणा रोड़वेज के निजीकरण के खिलाफ और हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव

(पृष्ठ 1 का शेष)

भी नियंत्रण मुक्त करने की बात कर रही है। यह फैसला पूरी तरह कार्पोरेट्स के हित में है। साथ ही पेट्रोल-डीजल के वास्तविक मूल्य से भी दोगुना टैक्स केंद्र व राज्य सरकारें आम जनता से वसूल रही हैं। म. प्र. सरकार का टैक्स महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा है। अगर सरकार की नियत महंगाई कम करने की होती, तो पेट्रोलियम पर दोगुना से ज्यादा टैक्स नहीं लगता। फिर भाजपा सरकार व इसके अनुयायी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने का हवाला देते हैं। पर सच्चाई यह है कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई, तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम 40 डालर प्रति बैरल के अपने रिकॉर्ड कमी पर थे। उस समय पेट्रोलियम के दाम लगभग 20 रुपये कम करने की स्थिति में सरकार थी। परंतु बड़ी-बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफे के लिए आम जनता पर इसकी मार जारी रही।

अब केंद्र की भाजपा सरकार रसोई गैस को भी नियंत्रण मुक्त करने की बात कर रही है। जबकि केंद्र सरकार ने कैश सब्सिडी के नाम पर सिलेंडर के दाम दोगुने से ज्यादा कर दिए हैं। सभी के खाते में सब्सिडी नियमित रूप से नहीं आ रही है। सरकार की उज्जवला योजना गैस कंपनियों को ग्राहक उपलब्ध कराने तक ही सीमित रही। उज्ज्वला योजना में गैस व चूल्हा प्राप्त किये लोगों से बाद में किस्तों में सब्सिडी में से कटौती करके रुपए वसूल किए गए। इसकी आड़ में रसोई गैस के दाम बढ़ा दिये गए। अधिकांश गरीब परिवार सिलेंडर महंगा होने के कारण दोबारा भरा पाने में सक्षम नहीं हो सके हैं। साथ ही इस योजना से लाभान्वित परिवारों को मिलने वाला केरोसिन भी बंद कर दिया गया है। आज महंगाई की मार से हर घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है। अगर बारीकी से विशेषण किया जाए, तो हम पाएंगे कि सरकार की जनविरोधी नीतियाँ ही इसके लिए जिम्मेदार हैं।

1991 की भूमंडलीकरण-उदारीकरण की नीति के बाद शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि सेवा क्षेत्रों में सरकारों ने बड़ी-बड़ी देशी- विदेशी कंपनियों को निवेश की छूट दे दी। रोजमर्रा के दैनिक उपयोगी सामानों पर पहले जहां सरकारी नियंत्रण कुछ हद तक काम करता था, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में दैनिक जनोपयोगी वस्तुओं के दाम कंट्रोल किए जाते थे लेकिन धीरे-धीरे सरकार ने पूरी राशन व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया एवं इन दुकानों पर से अपना नियंत्रण हटा लिया। इसके परिणामस्वरूप देखा जा रहा है कि खाद्यान्न, कृषि उपज किसानों से तो सस्ती से सस्ती कीमत पर खरीद ली जाती है, पर इन्हीं कंपनियों के द्वारा उसका असीमित भंडारण करने के बाद में महंगे से महंगे दामों में बेचा जाता है। अगर कृषि उपज की खरीद वितरण सरकार स्वयं अपने हाथ में लेती, तो निश्चित रूप से खाद्यान्न उत्पादक किसानों को भी फायदा मिल पाता और आम जनता को भी महंगाई से राहत पहुंच पाती। लेकिन अफसोस आम जनता के वोट से जीतने वाली पार्टियाँ सत्ता के पक्ष व विपक्ष में रहते हुए भी काम पूंजीपतियों के लिए ही करती हैं।

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी),खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम एवं नोटबंदी जैसे जनविरोधी कदमों की वजह से धीरे-धीरे छोटे व लघु उद्योग-धंधे बंद होते जा रहे हैं। इनसे महंगाई और भी भयावह रूप ले चुकी है क्योंकि जीएसटी के माध्यम से अब वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं पर भी टैक्स की दरें भी बढ़ा दी हैं और दायरा भी। इसी प्रकार खुदरा व्यापार में एफडीआई को मंजूरी देने से खाद्यान्न के कारोबार में देशी-विदेशी बड़ी एकाधिकारी पूंजी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बेरोजगारी के भयावह हालात

बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ग्वालियर में 57 चपरासी पदों के लिए 64000 आवेदन आए, तो पूरा प्रदेश सकते में आ गया। हैरत की बात तो यह है कि इनमें कई हजार पीएचडी, एमबीए डिग्री वाले लोग थे। इसी तरह गत वर्ष पटवारी के 9325 पदों के लिए 12 लाख युवाओं ने आवेदन किया। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2015 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 15 लाख 60 हजार थी, वहीं 2017 में यह बढ़कर 23 लाख 70 हजार को पार कर चुकी है। जबकि उनको भी शामिल किया जाए जो पंजीकृत नहीं हैं, तो बेरोजगारी का असल आंकड़ा और भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट में कहा गया, कि वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश के 48 रोजगार कार्यालयों ने मिलकर मात्र 334 लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराया।

प्रदेश की भाजपा सरकार, युवाओं को रोजगार देने के बजाय हजारों रिक्त पड़े शासकीय पदों को खत्म कर रही है। स्थाई पदों पर संविदा व ठेके पर भर्ती की जा रही है। जिनमें युवाओं से न्यूनतम वेतन पर अधिकतम काम लिया जा रहा है। जिन रिक्त पदों पर भर्ती निकाली भी जा रही है, उनमें आवेदन शुल्क के नाम पर सरकार बेरोजगारों की जेबों पर डाका डालने का काम कर रही है। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सभी बेरोजगारों को रोजगार दे और जब तक रोजगार मुहैया न कराए जायें, तब तक उन्हें जीवन जीने लायक बेरोजगारी भत्ता दे। लेकिन सरकार इसकी जगह विभिन्न आवेदनों पर 500 -1000 रुपये ऐंठ रही है।

माननीय प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के अपने वायदे की विफलता को ढंकते हुए, उच्च शिक्षित बेरोजगारों को पकोड़े तलने और पंचर जोड़ने की सलाह दे रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में ही इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में हजारों लाखों रेहड़ी-पटरी, ठेले वालों को सड़कों से खदेड़ रहे हैं ? लोगों के घर दुकान उजाड़े जा रहे हैं। फिर सवाल यह भी है कि क्या सभी बेरोजगार पकोड़े तलेंगे? क्या आप किसी को सड़क किनारे पकोड़े तलने का व्यवसाय भी करने देंगे!! आज खुदरा व्यापार में एफडीआई लाकर वैसे ही आपने आम लोगों के व्यापार को ठप्प कर दिया है। ऐसे में कौशल विकास का झांसा दिया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले वर्षों में मोदी सरकार ने लगभग 4 लाख 50 हजार पदों को खत्म किया है। फिर 3000-4000 रुपए प्रतिमाह का रोजगार, रोजगार की श्रेणी में नहीं आता! एक मुकम्मल रोजगार वही माना जाता है जिसमें गरिमामय ढंग से अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण हो सके, जिसमें किसी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ जमा पूंजी हो और जिसमें कुछ वृद्धावस्था की सुरक्षा हो। लेकिन अफसोस आज सरकार स्वयं शासकीय नौकरियों से ये सारी सुविधाएं खत्म कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सभी विभागों में स्थाई काम के लिए स्थाई नियुक्ति न करके ठेका या संविदा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। जबकि आशा-उषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहयोगिनी एवं अन्य विभागों के ठेका श्रमिक सरकार से समान काम के समान वेतन एवं नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने मजदूरों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। पिछले 4 वर्षों में श्रम कानूनों में होने वाले विभिन्न बदलाव ने मजदूरों के जीवन को अनिश्चितता से भर दिया है। नोटबंदी के दौरान मध्य प्रदेश में हजारों लघु उद्योग-धंधे बंद हो गए हैं। अकेले बुराहनपुर जिले में नोटबंदी के 22 दिनों में 15 हजार से अधिक पावरलूम बंद हो गए।(30 नवम्बर, 2016 भास्कर) जबकि दूसरी तरफ मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार हर साल निवेशकों को आमंत्रित करते हुए 'इंवेस्टर्स सम्मिट' का ढोंग कर लाखों रुपये बर्बाद कर रही है जबकि हकीकत यह है कि बाजार में छाई घोर मंदी के दौर में उद्योगपति कोई बड़ा निवेश परम्परागत उत्पादन में लगाने की स्थिति में नहीं हैं।

आज हजारों लाखों छात्र बड़ी-बड़ी डिग्रियां हाथों में लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। नौकरियों के नाम पर झांसा देने का कारोबार चरम पर है। महिलाओं व बच्चियों को रोजगार के नाम पर गुमराह कर देह-व्यापार में धकेलने जैसी खबरें दिनों दिन बढ़ रहीं हैं। सरकार निजी संस्थानों को फायदा पहुंचाने के लिए डिग्री-डिप्लोमा के कारोबार के माध्यम से छात्र नौजवानों के साथ धोखाधड़ी में लिप्त हैं। छात्र-नौजवानों के गरीब परिवारों की संचित निधि को दांव पर लगाया जाता है। सरकार और प्राइवेट कंपनियों के इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाने से एवं समाज व परिवार के तंज सुनने की क्षमता खोकर आज छात्र-नौजवान हताशा व निराशा में डूब कर या तो नशाखोरी व अन्य अनैतिक कार्यों में लिप्त होते जा रहे हैं या फिर अपने सामने कोई विकल्प नहीं पाकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में ही प्रतिदिन चार बेरोजगार युवा काम न मिलने के कारण मौत को गले लगा रहे हैं।

ऐसी भयावह परिस्थिति में सरकार बेरोजगारी के सही कारण पर पर्दा डाल रही है और अपनी नाकामी को छुपाते हुए बेरोजगारों को आरक्षण जैसे मुद्दों में उलझा कर रख रही है। जबकि हकीकत यह है कि सरकार लाखों-लाख पद खत्म कर रही है। इसी तरह युवाओं में क्षेत्रवाद को पनपा कर विभिन्न प्रदेशों में रह कर रोजी-रोटी कमा रहे अन्य राज्यों के लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं। वैमनस्य की खाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

बदहाल किसान खेत-मजदूर

किसानों की दर्दनाक कहानी है। मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। 2011 से 2016 के बीच 6071 किसानों ने आत्महत्या की है। किसान आत्महत्या के मामले मध्य प्रदेश में 21% बढ़े हैं। पूरे देश में पिछले 15 वर्षों में लगभग साढ़े तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है। म. प्र. के लाखों किसान-खेत मजदूर पलायन कर रहे हैं। लाखों ग्रामीण मजदूर शहरों में काम की तलाश में आ रहे हैं। बुंदेलखंड इलाके में स्थिति और भी भयावह है। यह आज गांव-देहात में खेती और किसान की हालत बयां करता है। बड़ी संख्या में किसान-खेत मजदूरों का रोजी रोटी के लिए पलायन का मायने ही है कि खेती अब स्वयं अन्नदाता को दो जून की रोटी मुहैया कराने में असमर्थ है। आज की स्थिति में कोई किसान खेती में अपने बच्चे का भविष्य नहीं देखता। बात तो यहाँ तक है कि अगर किसान को कोई काम का विकल्प मिले, तो वह खेती ही नहीं करे क्योंकि आज खेती करने का मतलब ही है नए कर्ज के जाल में फंसना।

दरअसल 1991 में दुनिया भर के पूंजीवादी साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने मिलकर अपने आर्थिक संकट से उबरने के लिए उदारीकरण-भूमंडलीकरण की नीति लागू की। इसके बाद से ही अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि को भी धीरे-धीरे देशी-विदेशी बाजार के लिए खोल दिया गया। कृषि पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को धीरे-धीरे ना सिर्फ खत्म कर दिया बल्कि कृषि में उपयोगी सामानों पर देशी-विदेशी कंपनियों के व्यापार की खुली छूट दे दी गई। इसी प्रक्रिया में धीरे-धीरे सरकारों द्वारा कृषि उत्पादों के वितरण से भी अपना नियंत्रण हटा लिया गया।

इसके बाद कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी के बाद किसान की हालत बद से बदतर होती चली गई। इन नीतियों के दुष्परिणामों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, कि पिछले 15 वर्षों में देश भर में लगभग साढ़े तीन लाख किसानों ने कर्ज के जाल में फंस कर अपनी जान दे दी। जैसा कि आज देखा भी जा रहा है कि एक तरफ किसानी की लागत लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ किसान को उसकी उपज की वाजिब दामों से वंचित किया जा रहा है। मूल बात तो यह है कि खाद, बीज, डीजल, बिजली आदि के दाम तय करने वाली भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं और किसान को उपज के दाम तय करने वाली भी यही हैं। ये देशी-विदेशी कंपनियां किसानों को खाद, बीज, डीजल, बिजली, कीटनाशक सभी कुछ अधिक दामों में बेचती हैं। किसान की उपज को कम से कम दामों में खरीद कर असीमित मुनाफा कमाती हैं। फल सब्जी के मामले में तो देखा गया है कि किसान को कभी-कभी सब्जियों जैसी कृषि उपज मंडी तक लाना भी महंगा पड़ता है। गत दिनों कई बार किसानों को मजबूरन आलू, प्याज, टमाटर आदि सड़कों पर फेंकना पड़ा है। कृषि उपज पर जारी वायदा बाजार के नाम से सट्टेबाजी के खेल ने कृषि उपज के भाव को अनिश्चितता से भर दिया है। यह दिखाता है कि किसान की पैदावार कम हो, तो भी किसान घाटे में हैं और अगर अच्छी पैदावार हो जाए, तब भी किसान घाटे में रहता है।

तब यह समझना होगा कि भाजपा-कांग्रेस जैसी पूंजीवादी पार्टियों की नीतियों का ही यह परिणाम है। ये पार्टिया अपनी सारी नीतियों को मजदूर किसान हितैषी बता कर लागू करती हैं। पर इससे फायदा सीधा बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश में बीमा कंपनियों ने किसानों से 1800 करोड़ रुपए वसूल किये और फसल बर्बादी पर मात्र 714 रुपये का क्लेम दिया।(14 फरवरी 2018 के दैनिक भास्कर) बीमा योजना की आड़ में सरकार ने फसल बर्बादी पर दिया जाने वाला मुआवजा खत्म कर दिया। म.प्र. में जोरशोर से लागू की गई भावांतर भुगतान योजना में बड़े-बड़े अनाज व्यापारियों ने कैसे फायदा उठाया,जिससे फसल के दाम धरातल पर आ गये। किसान आज भी अपनी उपज के दामों के भुगतान के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे हैं।

इसी तरह नोटबंदी के दौरान व उसके बाद भी कृषक समुदाय ही सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है। भाजपा सरकार ने नवंबर 2016 में नोटबंदी उस समय की, जब किसान अपनी फसल लेकर कृषि उपज मंडी में खड़ा था। उसे रुपयों की तब सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि खरीफ की फसल का कर्ज चुकाना था और आगामी रबी की फसल के लिए जरूरी खाद बीज खरीदना था। किसान की तो जैसे जिंदगी ही रुक गई थी, उस दौरान रुपए निकालने की लंबी-लंबी कतारों में भूख-प्यास धूप से पीड़ित जनता में सबसे ज्यादा व्यथित समुदाय किसान

(शेष पृष्ठ 6 पर)

आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव

भाजपा की एकाधिकारी पूंजीपतिपरस्त जनविरोधी नीतियों, कांग्रेस व अन्य दलों की अवसरवादी वोट की राजनीति को परास्त करें

पिछले 15 वर्षों से बीजेपी शासन के तहत रहा छत्तीसगढ़ अब 12 और 20 नवंबर 2018 को दो चरणों में होने वाले 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने आठवें विधानसभा चुनाव से रूबरू है। वर्तमान बीजेपी सरकार ने श्री अजीत जोगी-नीत कांग्रेसी सरकार की जगह ली थी, जो अब तक के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि इसकी उम्मीद की जा सकती है, कांग्रेस की तरह शासक बुर्जुआ वर्ग की एक और सबसे भरोसेमंद पार्टी बीजेपी की सरकार ने इसके शासनकाल में राज्य में लोगों के जीवन को और अधिक दुखी बना दिया। उद्योग दिन पर दिन निरंतर बंद हो रहे हैं। देश की पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ी बेरोजगारी, गरीबी और अन्य सभी व्याधियों ने लोगों को बर्बादी के कगार पर लाने में कई गुना वृद्धि दर्ज की है। राजधानी शहर रायपुर में औद्योगिक श्रमिकों को दिन में 100 से 125 रुपये के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी सरकार ने एक नया रायपुर शहर बनाने के नाम पर विकास के बहाने 15000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सभी केंद्रीय और राज्य सरकारी संगठन कर्मचारियों की नियुक्तियाँ अनुबंधित आधार पर कर रहे हैं या उनकी गतिविधियों को निजी मालिकों के हवाले किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभागों में दो लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। न केवल निजी उद्योगों और संगठनों में बल्कि सरकारी संस्थानों में भी संविदा या ठेके पर लगाए गए श्रमिकों की मजदूरी निहायत कम है। किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर भूमिहीन श्रमिकों में बदल दिया है, कृषि भूमि को तेजी से अमीर लोगों को तोहफे में दिया जा रहा है। वे किसान जो अभी भी अपनी भूमि पर कब्जा रख सकते हैं, उनकी फसल के लिए पर्याप्त समर्थन मूल्य देने से निर्दयतापूर्वक इनकार कर दिया जाता है। यह भयंकर स्थिति पिछले 15 वर्षों में 11500 किसानों की आत्महत्याओं के बहुत ही कम आंके हुए रिकॉर्ड से भी स्पष्ट हो गई है। पिछले साल बड़े भारी सूखे के बावजूद, किसानों को सरकार से कोई बीमा लाभ नहीं मिला। इसके विपरीत, उन्हें निजी कंपनियों से फसल बीमा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा मजबूर किया गया। जबकि विशेषाधिकार प्राप्त, अमीरों और पूंजीपतियों के लिए नजारा बिल्कुल उलट है। राज्य खनिजों के अपने समृद्ध संसाधनों के लिए जाना जाता है। अब बीजेपी सरकार बेहिचक सभी खानों और अन्य संबन्धित उद्योगों को पूंजीपतियों को सौंप दे रही है जो अब तक राज्य के स्वामित्व में थीं। इस प्रक्रिया ने आग में घी डालने की तरह बेरोजगारी और हर तरह के शोषण को बेइन्तहा बढ़ा दिया है, जिससे निजी मालिकों ने मुनाफे के अम्बार लगाए हैं। बेरोजगारी और गरीबी का असहनीय डंक लाखों गरीब लोगों को किसी भी कीमत पर कहीं भी काम की तलाश में राज्य से बाहर पलायन करने को मजबूर कर रहा है। ऐसे लाखों लोग, स्वाभाविक रूप से युवा ही इनमें ज्यादा हैं, पहले ही स्थायी रूप से प्रवासी हो चुके हैं।

कई हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है या निजी मालिकों को सौंप दिया जा रहा है। ऐसे ही अस्पतालों का निजीकरण किया जा रहा है। दूसरी तरफ, शराब व्यवसाय जो अब तक निजी हाथों में रहा है, देखा जा रहा है कि सरकार राजस्व अर्जित करने के बहाने पिछले दो वर्षों में बढ़चढ़ कर इसे अपने हाथों में लेती जा रही है। नतीजतन, राज्य ने 2017-18 में 5800 करोड़ रुपये का राजस्व वसूलने का गौरव अर्जित किया है, जो कई राज्यों की राशि से अधिक है। लेकिन नतीजतन, शराब का व्यापक उपयोग परिवारों और लोगों के जीवन को नष्ट कर रहा है। समाज में शराब की खपत के इस भयानक फैलाव के खिलाफ पीड़ित लोगों का एक स्वत:स्फूर्त आंदोलन चला। हमारी पार्टी ने भी कुछ क्षेत्रों में बढ़ती शराबखोरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए आन्दोलन किए। लेकिन इस सरकार ने बस लोगों की पुरजोर अपीलों को अनसुना कर दिया। इस तरह बीजेपी सरकार जो मूल्य-आधारित होने का दावा करती है, लोगों को अनैतिक कृत्य करने और अनैतिक जीवन जीने की ओर धकेल देती है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। यही बीजेपी सरकार बहुत सारे घोटालों में संलिप्त है, जैसे कि पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम) घोटाला, जो कई हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, कोयला ब्लॉक घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला आदि। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने खुद अपने मंत्रियों और पार्टी के नेताओं से कम से कम एक साल तक 'कमीशन' खाना बंद करने को कहा ताकि भाजपा अपनी छवि को फिर से सुधार सके और 30 साल तक अपना शासन जारी रख सके। हालांकि, उनके बेटे और बीजेपी के सांसद अभिषेक सिंह का नाम कुख्यात पनामा पत्रों में पाया गया। इस तरह की 'मूल्य-आधारित' पार्टी है जो मतदाताओं को मुफ्त तोहफे और रिश्वत देकर रिझा रही है। वोट राजनीति में कुछ लाभ हासिल करने के लिए, बीजेपी सरकार ने पूरे राज्य में कॉलेज के छात्रों और बीपीएल परिवारों को सार्वजनिक राजकोष से कुछ सौ करोड़ रुपये का उपयोग करके पचास हजार एंड्रॉइड मोबाइल फोन वितरित किए हैं। सत्ता में बीजेपी के आने के साथ सांप्रदायिक घृणा में कई गुना वृद्धि हुई है। संकीर्ण क्षेत्रीयता को भी उकसाया है। साथ ही, यह वामपंथ और मार्क्सवाद के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। तथाकथित माओवादी समस्या से निपटने के नाम पर, सरकार अपने तमाम दमनकारी अमले के साथ आदिवासी लोगों पर भारी कहर बरपा रही है, उन्हें बेखटके मौत के घाट उतारा जा रहा है। मीडिया के जिन लोगों ने आगे आने और बीजेपी सरकार और उसके प्रशासन के कष्टों का पर्दाफाश करने का साहस किया, उन्हें बेबुनियाद और झूठे गढ़े हुए आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है, यहां तक कि राज्य छोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया है। सरकार और पूंजीपतियों के खिलाफ कोई खबर प्रकाशित नहीं की जा रही है। वस्तुत: राज्य में अघोषित प्रेस सेंसरशिप लगाई हुई है।

कांग्रेस ने बीजेपी के कष्टों के खिलाफ व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय और चुप रहना पसंद किया था। बल्कि, भाजपा सरकार की एकाधिकारी पूंजीपति परस्त नीतियों के समर्थन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खड़े होकर कांग्रेस सत्ता-सुख पाने के लिए वोट की राजनीति में भाजपा के मुकाबले में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सीपीआई और सीपीआई(एम), अभी भी बड़े वाम दल होने का दावा कर रही हैं, कम से कम लोगों को कुछ राहत दिलाने के लिए जोरदार जनआंदोलन गठित किए बिना फौरी लाभ पाने के लिए केवल संसदीय राजनीति पर अमल कर रही हैं। 2008 के विधानसभा चुनावों में सीआईटीयू ने भिलाई निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने वाली एक पुस्तिका को खुले तौर पर वितरित किया, भले ही सीपीआई ने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर रखा था। बाद में, 2013 के विधानसभा चुनावों में, सीपीआई और सीपीआई (एम) ने बीजेपी के दो बार विधायक और चार बार सांसद रह चुके भाजपा से निष्कासित नेता द्वारा बनायी गई एक कट्टरपंथी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन किया। इस बार 2018 के विधानसभा चुनावों में, सीपीआई और सीपीआई(एम) दोनों ने निर्णय लिया था कि भाजपा को सत्ता से हटाना चुनाव में उनका मुख्य लक्ष्य और उनकी नीति थी। और इस अंत तक पहुंचने के लिए, उन्होंने प्रत्येक सीट पर संभावित दूसरे विजेता उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया, जिसमें राज्य में, सभी संभावनाओं में कांग्रेस होगी। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि कांग्रेस भाजपा का विकल्प है। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी, हालांकि बाद में, उसने उनके अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन सीपीआई इन सभी हथकण्डों के बाद अचानक बीएसपी और कांग्रेस के भ्रष्ट पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा गठित क्षेत्रीयता के आधार पर बनायी हुई एक पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गई। हमारी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट), सीपीआई, सीपीआई (एम) और सीपीआई एमएल-लिबरेशन को लेकर वाम दलों का मोर्चा या गठजोड़ बनाया गया। इस गठजोड़ ने लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन सीपीआई ने बीएसपी-कांग्रेस (जे) गठबंधन में अपने नए सहयोगियों को ढूंढकर 13 सीटों से अपने उम्मीदवार वापस ले लिये और 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद, सीपीआई (एम) ने सीपीआई (एमएल) से भिलाई सीट से नहीं लड़ने को कहा क्योंकि सीपीआई (एम) सीपीआई (एमएल) उम्मीदवार का समर्थन करने की बजाय कांग्रेस को अपना समर्थन सुनिश्चित करेगी। यह वह गंदलाया हुआ भद्दा नजारा है जो ये तथाकथित मार्क्सवादी पार्टियाँ अपने तुच्छ संसदीय लाभ के लिए पेश कर रही हैं।

देश की क्रांतिकारी पार्टी के रूप में, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतन से लैस, हमारी पार्टी ने लोगों के जीवन की विभिन्न महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्याओं पर जनआंदोलन गठित करने की भरसक कोशिश की है जो हमारे पास हो सकता है। हमने शराब पर पूर्ण रोक लगानी की मांग को लेकर आंदोलन गठित करने में अपनी पूरी ताकत झौंक दी थी। उस मुद्दे पर हमारी पार्टी के दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा हमने राज्य में गहन सांस्कृतिक पतन के खिलाफ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। संसदीय मंच से लोगों की आवाज उठाने के लिए, इन संसद के बाहर चलाए गए आंदोलनों के साथ-साथ पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में **कॉ. आत्माराम साहू** और **कॉ. पद्म पाटिल** को क्रमश: दुर्ग शहर और अहिवारा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। हम एसयूसीआई (सी) के उम्मीदवारों को विजयी बनाने और जहां हमारी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, वहां उपलब्ध वामपंथी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने की लोगों से अपील करते हैं ताकि विधानसभा में लोगों की आवाज उठायी जा सके।

कश्मीर में धारा-35ए न हटायी जाए –एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)

कश्मीर से संबंधित भारतीय संविधान की धारा 35ए को रद्द करने के सत्तारूढ़ बीजेपी के कदम का विरोध करते हुए एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 7 अगस्त 2018 को निम्नलिखित बयान जारी किया :

भारत की आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा हमला किए जाने के बाद, शेर-ए-कश्मीर के नाम से मशहूर अपने लड़ाकू नेता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर के लोगों ने भारत सरकार के साथ कश्मीर के विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत में कश्मीर का विलय करने का विकल्प चुना। इस विलय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त थी कश्मीर की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण कश्मीर के लोगों की स्वायत्तता की सुरक्षा और अंत में धारा 370 को भारत के संविधान में जोड़ना। तदनुसार, तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। लेकिन, शुरुआत से ही, कांग्रेस या बीजेपी जैसे केंद्र में सत्तारूढ़ बुर्जुआ दलों द्वारा नौकरशाही का बोलबाला कायम करने और समझौते के प्रावधानों के निरंतर उल्लंघन के कारण कश्मीर के लोगों में शिकायतें और असंतोष जमा होता गया।

धारा 370 के प्रावधानों को लागू करने के बजाय, पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी की अगुआई वाली केंद्रीय सरकार ने क्रूर सैन्य और अर्धसैनिक दमन-उत्पीड़न के सहारे जन विक्षोभ को दबाये जाने ने संकट को बढ़ा दिया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ चरमपंथी और अलगाववादी ताकतों ने वहां अपने सिर उठाए। इसके अलावा, धारा 370 रद्द करने की बीजेपी की मांग ने संकट को और भी बढ़ा दिया है।

हमारा मानना है कि केंद्र सरकार ने अगर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया होता और राजनीतिक वार्ता का तरीका इस्तेमाल किया होता, तो इस संकट को बढ़ने से रोका जा सकता था। दूसरी तरफ, सरकार ने सैन्य दमन-उत्पीड़न में वृद्धि का विकल्प चुना और जितना दमन-उत्पीड़न बढ़ रहा है, लोगों का विरोध और विक्षोभ भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। चरमपंथियों का मुकाबला करने के दौरान, कई निर्दोष लोगों की मौत हो गई और घायल हो गए। ऐसी स्थिति में, बीजेपी ने जानबूझ कर धारा-35ए रद्द करने की मांग उठाई है जिससे कश्मीर के लोगों के बीच संपत्ति, जायदाद और अन्य अधिकारों को खोने का जबरदस्त डर पैदा हो गया है, इस प्रकार जन असंतोष और विरोध अधिक तीव्र होता दिख रहा है।

हम कश्मीर समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार को पहल करने के लिए मजबूर करने के लिए निम्नलिखित मांगों पर आंदोलन गठित करने के लिए देश के सभी वामपंथी व लोकतांत्रिक दलों, संगठनों, लोगों और बौद्धिक समुदायों से आग्रह करते हैं। एक) धारा-370 पूरी तरह लागू की जाए। दो) धारा-35ए को रद्द करने की मांग वापस ली जाए। तीन) सैन्य और अर्ध-सैन्य बलों द्वारा किए जा रहे दमन-उत्पीड़न को रोका जाए और राजनीतिक प्रक्रिया के जरिये कश्मीर समस्या को हल किया जाए।

हम कश्मीर के लोगों से अपील करते हैं कि वे उत्तेजना और भ्रम का शिकार न हों बल्कि कश्मीर समस्या को हल करने के लिए आंदोलन विकसित करने के लिए भारत के लोकतांत्रिक लोगों के साथ एकजुट हो जाएं।

तीसरी पार्टी कांग्रेस से पहले राज्य सम्मेलन सम्पन्न

हमारी पार्टी एसयूसीआई (सी) की तीसरी कांग्रेस से पहले विभिन्न राज्यों में राज्य सम्मेलन सम्पन्न हुए। इनके सत्र शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुए। सम्मेलन स्थल पर लाल झण्डा भी फहराया गया। सत्र की शुरुआत में कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत गाया गया। प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर थीसिसों के साथ-साथ राज्य की संगठनात्मक रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। अंतर्राष्ट्रीय गान के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

असम : केन्द्रीय कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सौमेन बसु और झारखंड राज्य सचिव कॉमरेड राबिन समाजपति की उपस्थित में 18-19 सितंबर को गुवाहाटी में आयोजित असम राज्य सम्मेलन में 25 सदस्यीय मजबूत नई स्टेट कमेटी गठित की गई जिसकी सचिव कॉमरेड चंद्रलेखा दास चुनी गई। तीसरी पार्टी कांग्रेस के लिए असम के प्रतिनिधियों के नाम भी घोषित किए गए।

मध्य प्रदेश : 10 जिलों के प्रतिनिधियों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य सम्मेलन 22-23 सितंबर को भोपाल में आयोजित किया गया था। केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड शंकर साहा, ओडिशा राज्य सचिव कॉ. धुर्जटी दास और यूपी स्टेट कमेटी के सदस्य कॉ. स्वप्न चटर्जी केन्द्रीय कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के रूप में उपस्थित थे। सचिव के रूप में कॉमरेड प्रताप सामल सहित 12 सदस्यीय मजबूत राज्य कमेटी सर्वसम्मति से चुनी गई।

कर्नाटक : कर्नाटक राज्य सम्मेलन 21 से 24 सितंबर को केंद्रीय कमेटी सदस्यों कॉमरेड के. राधाकृष्ण और सौमेन बसुं, केरल राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉमरेड वी. वेणुगोपाल और पश्चिम बंगाल राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉ. सुभाष दासगुप्त की उपस्थिति में गुलबर्गा में आयोजित किया गया। राज्य सचिव के रूप में कॉमरेड के उमा को लेकर 12 सदस्यीय मजबूत नई स्टेट कमेटी सर्वसम्मति से सम्मेलन से निर्वाचित हुई।

बिहार : बिहार राज्य सम्मेलन 7 और 8 अक्टूबर को जमालपुर (मुंगेर) में केन्द्रीय कमेटी की ओर से पर्यवेक्षक केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सत्यवान, झारखंड राज्य सचिव कॉ. राबिन समाजपति, ओडिशा राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉ. शंकर दासगुप्त और यूपी राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉ. स्वप्न चटर्जी की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। कॉमरेड अरुण कुमार सिंह को राज्य सचिव लेकर 15 सदस्यीय मजबूत स्टेट कमेटी सर्वसम्मति से चुनी गई।

दिल्ली : दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी का राज्य सम्मेलन 30 सितंबर, को केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड शंकर साहा और मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति और राष्ट्रीय परिस्थितियों पर थीसिसें के मसौदे पर चर्चा-बहस के बाद और राज्य सचिव की राजनीतिक और सांगठनिक रिपोर्ट के सर्वसम्मति से पारित करने के बाद, 7 सदस्यीय राज्य सांगठनिक कमेटी कॉमरेड प्राण शर्मा के सचिव के रूप में लेते हुए चुनी गई।

हरियाणा : 24-25 अक्टूबर को गुरुग्राम की प्रजापति चौपाल में केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड शंकर साहा और बिहार राज्य सचिव कॉमरेड अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में हरियाणा राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। कॉमरेड सत्यवान को सचिव के रूप में लेकर 21 सदस्यीय एक नई राज्य कमेटी चुनी गई।

महाराष्ट्र, मुंबई : मुंबई जिला सम्मेलन 7 अक्टूबर को केन्द्रीय पर्यवेक्षक के रूप में स्टाफ सदस्य कॉ. द्वारिकानाथ रथ की उपस्थिति में आयोजित किया गया। सचिव के रूप में कॉमरेड अनिल कुमार त्यागी को लेकर एक नई 4 सदस्यीय जिला कमेटी चुनी गई।

झारखंड : दूसरा झारखंड राज्य सम्मेलन 23 अक्टूबर को केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सौमेन बसु, ओडिशा राज्य सचिव कॉ. धुर्जटी दास, और बिहार राज्य सचिव कॉ. अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में रांची में राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉमरेड के. डी. सिंह, की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सचिव के रूप में कॉमरेड राबिन समाजपति को लेकर 13 सदस्यीय राज्य सांगठनिक कमेटी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुई।

ओडिशा : तीसरा ओडिशा राज्य सम्मेलन भुवनेश्वर में 27-28 अक्टूबर को आयोजित किया गया। केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सौमेन बसु, पश्चिम बंगाल राज्य सचिवमण्डल सदस्य सदस्य कॉमरेड स्वप्न घोष और चंडीदास भट्टाचार्य, और असम राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉ. कांतिमय देव केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में उपस्थित थे। इस सम्मेलन का संचालन ओडिशा राज्य कमेटी के सदस्यों कॉमरेडस बिष्णु दास, वीणापाणि दास और रघुनाथ दास को लेकर बने एक अध्यक्षमण्डल द्वारा किया गया। सम्मेलन ने कॉमरेड धुर्जटी दास को राज्य सचिव के रूप में लेकर 30 सदस्यीय मजबूत नई स्टेट कमेटी चुनी गई।

केरल

हमारी पार्टी का तीसरा केरल राज्य सम्मेलन 12, 13 और 14 अक्टूबर को त्रिचुर शहर में साहित्य अकादमी हाल में आयोजित किया गया। केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड के. राधाकृष्ण, पश्चिम बंगाल राज्य सचिवमण्डल सदस्य अमिताभ चटर्जी और सुभाष दासगुप्त केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में उपस्थित थे। लंबी बीमारी के कारण केन्द्रीय कमेटी के सदस्य और केरल राज्य सचिव कॉमरेड सी. के. ल्यूकोस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके। उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में एक चिकित्सा बुलेटिन पढ़ा गया। कॉमरेड जी. एस. पद्मकुमार और ए. जलालुद्दीन सहित पार्टी के दिवंगत नेताओं और पार्टी के संगठकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक शोक प्रस्ताव कॉमरेड मिनी के. फिलिप द्वारा पेश किया गया। सचिव के रूप में कॉमरेड वी. वेणुगोपाल को लेकर 20 सदस्यीय मजबूत स्टेट कमेटी सर्वसम्मति से चुनी गई।

उत्तर प्रदेश : यूपी स्टेट कन्वेंशन 28-29 अक्टूबर को मुरादाबाद में आयोजित किया गया। केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड सत्यवान, बिहार राज्य सचिव अरुण कुमार सिंह और झारखंड राज्य सचिव कॉ. रॉबिन समाजपति केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में उपस्थित थे। कॉमरेड पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा को सचिव के रूप में लेकर 26 सदस्यीय मजबूत राज्य सांगठनिक कमेटी सम्मेलन से चुनी गई।

आंध्र प्रदेश : 27-28 अक्टूबर को अनंतपुर में आंध्र प्रदेश राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड के. राधाकृष्ण, स्टाफ सदस्य कॉमरेड के. श्रीधर, कर्नाटक राज्य सचिव कॉमरेड के. उमा और पश्चिम बंगाल राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉ. अमिताभ चटर्जी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया सम्मेलन में सचिव के रूप में कॉमरेड बी. एस. अमरनाथ को लेकर 7 सदस्यीय मजबूत राज्य सांगठनिक कमेटी चुनी गई।

तमिलनाडु : 21-22 अक्टूबर को चेन्नई में चेपॉक स्थित मद्रास रिपोर्टर गिल्ड हाल में तमिलनाडु राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड के. राधाकृष्ण, पश्चिम बंगाल राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉ. शंकर घोष, और स्टाफ सदस्य कॉमरेड के श्रीधर केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में उपस्थित थे। पार्टी के तमिलनाडु राज्य सचिव कॉमरेड ए. रंगास्वामी ने अध्यक्षता की। सम्मेलन ने 12 सदस्यीय राज्य सांगठनिक कमेटी चुनी जिसमें कॉमरेड ए. रंगास्वामी सचिव लिए गए।

गुजरात : अहमदाबाद में 14-15 अक्तूबर को दो दिन गुजरात राज्य सम्मेलन केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉ. शंकर साहा की उपस्थिति में हुआ। सम्मेलन में कॉ. मीनाक्षी जोशी को सचिव के रूप में लेते हुए 18 सदस्यीय नई गुजरात राज्य सांगठनिक कमेटी का गठन किया गया।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

हरियाणा रोड़वेज के...

(पृष्ठ 1 का शेष)

गुरुग्राम

हो रही है उसमें यह अपेक्षा की जाती है कि तमाम विपक्षी पार्टियाँ सड़कों पर उतर कर इसका प्रतिरोध करें। इस संबंध में 31 अक्तूबर के विरोध दिवस को सफल बनाने के लिए अन्य विपक्षी नेताओं से भी व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने की अपील की गई है।

गौरतलब है कि रोड़वेज कर्मचारी 16 अक्तूबर से परिवहन विभाग के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं। प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी 26 अक्तूबर को सामूहिक अवकाश लेकर सरकार द्वारा निजी बसें किराए पर लेने का विरोध कर चुके हैं और अब कर्मचारियों के 150 से ज्यादा संगठनों ने 30-31 अक्तूबर को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हरियाणा रोड़वेज विभाग के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदेश के गांवों से जनता रोड़वेज कर्मचारियों के समर्थन में आ रही है। हरियाणा सरकार इसके बावजूद हठधर्मीपूर्ण रवैया अपनाए हुए है।

मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों को नीतिगत सवालों पर बोलने से मना करने की निंदा करते हुए वामपंथी पार्टियों ने कहा कि कर्मचारी भी जनता का हिस्सा हैं और उन्हें नीतिगत सवालों पर बोलने का पूरा हक है। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने चुनाव लड़ते समय रोड़वेज का निजीकरण करने की बात अपने घोषणा-पत्र में नहीं कही थी। अब भाजपा चुनावी वायदों के खिलाफ जाकर सरकारी विभाग व जनता की सुविधाओं की कीमत पर निजी बस मालिकों के हित में काम करने पर तुली हुई है। दरअसल इस नीति के तहत जिन शर्तों पर निजी बसें ली जा रही हैं वे निजी मालिकों को अकूत मुनाफे और परिवहन विभाग को भारी घाटे की गारंटी करती हैं। किलोमीटर आधार पर किराए पर निजी बसें लेने का जनहित से कोई वास्ता नहीं है।

वामपंथी पार्टियों ने सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ प्रदेशभर में सक्रिय होकर 31 अक्तूबर के विरोध प्रदर्शनों में बढ़चढ़कर शामिल होने की सभी पंचायत प्रतिनिधियों, जनसंगठनों, सामाजिक संगठनों, छात्रों व आम नागरिकों से अपील की।

रेवाड़ी

सूचना

सर्वहारा दृष्टिकोण, वर्ष 33, अंक-17, 18, 19 व 20 टैक्नीकल कारण से हम छाप नहीं पाये। इससे पाठकों को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है। –सम्पादक, स. दृ.

कॉमरेड भवानी शंकर घोष नहीं रहे

एसयूसीआई (सी) की मध्य प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी के पूर्व सदस्य कॉमरेड भवानी शंकर घोष ने 71 वर्ष की उम्र में कलकत्ता हार्ट क्लिनिक और अस्पताल में 12 अक्टूबर 2018 को अपनी आखिरी सांस ली, वे 2010 से विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त थे।

कॉमरेड भवानी शंकर घोष का जन्म वर्ष 1947 में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जयनगर-माजिलपुर में हुआ था। बचपन में, गंभीर आर्थिक संकट के कारण, वे पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में अपनी बड़ी बहन के घर गए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वहां रहे। 1966 में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, वे वापस जयनगर-माजिलपुर आए और अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू की। वे सबसे पहले उनके बचपन के दोस्तों में से एक कॉमरेड गोवर्धन प्रमानिक के माध्यम से कॉमरेड शिवदास घोष चिंतन के संपर्क में आए। कॉमरेड प्रामाणिक उन्हें तत्कालीन पालिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड सचिन बनर्जी के पास ले गए। कॉमरेड सचिन बनर्जी के साथ पूरी तरह से चर्चा के बाद, उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। 1969 में, कॉमरेड भवानी शंकर घोष मध्य प्रदेश के जबलपुर में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम गन कैरिज फैक्ट्री में नियुक्त हो गए।

1973 में, उन्होंने कोलकाता में एक राजनीतिक क्लास में भाग लिया, जिसका संचालन हमारी पार्टी के संस्थापक महासचिव और सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने किया था। इस क्लास ने नए सिरे से उन्हें मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतन की महान विचारधारा से लैस किया और उन्होंने अपनी दोस्त मण्डली को जुटा करके जबलपुर में पार्टी कार्य शुरू किया। उन्होंने गन कैरिज फैक्ट्री में ट्रेड यूनियन गतिविधियों की भी शुरुआत की। इनके साथ ही साथ, उन्होंने विभिन्न जन आंदोलन और प्रगतिशील सांस्कृतिक गतिविधियां करने में पहल की। इनके अलावा, उन्होंने लगातार अपने रिश्तेदारों को कॉमरेड शिवदास घोष

जबलपुर (म.प्र.) में कॉ. भवानी शंकर घोष स्मृति सभा में श्रद्धांजलि देते हुए पार्टी की जिला प्रभारी कॉ. चन्द्रा पात्रा

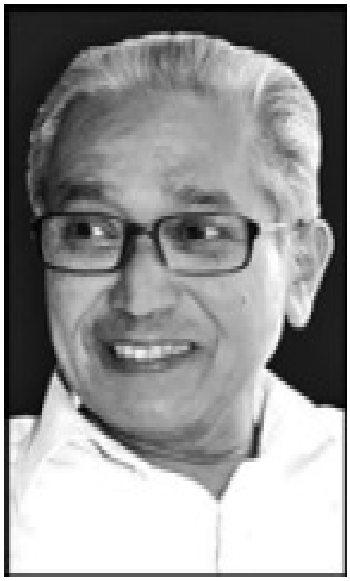

चिंतन से परिचित कराने की कोशिश की और उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने के लिए अत्यधिक प्रयास किए।

1976 में, कॉमरेड भवानी शंकर घोष ने अन्य लोगों के साथ मिल कर जबलपुर में शरतचंद्र जन्म शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में से एक, कॉमरेड माणिक मुखर्जी, अब हमारी पार्टी के एक पोलिट ब्यूरो सदस्य, जबलपुर में मुख्य वक्ता के रूप में गए थे। कार्यक्रम के बाद, पार्टी की जबलप्लुर जिला सांगठनिक कमेटी का गठन कॉमरेड माणिक मुखर्जी की उपस्थिति में हुआ था जिसके प्रभारी कॉमरेड भवानी शंकर घोष बनाये गए थे।

उस अवधि के दौरान, सागर और भोपाल जिलों में भी पार्टी की गतिविधियां शुरू हुई। 1980 में, मध्य प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी का गठन किया गया और कॉमरेड भवानी शंकर घोष उस कमेटी के सदस्य बने। वे एआईयूटीयूसी, मध्य प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य भी बने।

1989 में, कॉमरेड भवानी शंकर घोष ने पूर्णकालिक पार्टी के काम के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया। वे जबलपुर के मेहनतकश लोगों के विभिन्न तबकों, मजदूरों के साथ-साथ बौद्धिक समुदाय के बीच भी बहुत लोकप्रिय थे। वे ललित कला में बहुत कुशल थे और रचनात्मक ज्ञान की तन्मयता से साधना में लीन विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों का अध्ययन करने की सराहनीय फिदरत रखने वाले थे। वे अपनी सादगी के साथ-साथ निराभिमानी और मिलनसार स्वभाव के कारण सभी को बहुत प्यारे थे।

2010 में, गंभीर बीमारी के कारण, उन्हें दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार के लिए कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से, वे कोलकाता में एक पार्टी सेंटर में रह रहे थे। अपनी गंभीर बीमारियों के बावजूद, उन्होंने अपनी पार्टी की गतिविधियां जारी रखी, बिना किसी विद्वेष के और मुस्कुराते हुए आलोचना स्वीकार की, हमेशा स्वयं को आलोचना के अधीन किया और अपने से बहुत कम उम्र के कामरेडों के नेतृत्व में कोई भी काम करने में उनमें कभी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उनमें जबरदस्त ज्ञान-पिपासा थी और वे बहुत पढ़ाकू थे। वे यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत उत्सुक थे कि पार्टी के कॉमरेड खुद को वैचारिक रूप से लैस करने के लिए जानबूझकर पढ़ने की आदत विकसित करें। ठहरने के स्थान पर, वे क्रांतिकारी उद्देश्य के साथ विभिन्न सामाजिक सेवाओं में भी शामिल होते थे। अपने अस्पताल में भर्ती होने के दिन भी, उन्होंने स्थानीय पार्टी कमेटी द्वारा संचालित स्कूल के छात्रों की मुफ्त कोचिंग क्लास में भाग लिया। तीसरी पार्टी कांग्रेस की पूर्व संध्या पर, वे कोलकाता जिला सम्मेलन में एक प्रतिनिधि थे। अपने पूरे जीवन में, उन्होंने अनुकरणीय सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखा जो क्रांतिकारी वर्ग संघर्षों और जन आन्दोलनों के निर्माण के कार्य में शामिल सभी को प्रेरणादायक होना चाहिए।

23 अक्टूबर को भोपाल में उनकी स्मृति सभा आयोजित की गई जिसमें एसयूसीआई (सी) की केंद्रीय कमेटी के सदस्य और एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा ने कॉमरेड भवानी घोष के क्रांतिकारी जीवन के विभिन्न प्रशंसनीय पहलुओं के बारे में बताया। 30 अक्टूबर को कोलकाता में उनकी याद में एक और सभा आयोजित की गई।

कॉमरेड भवानी शंकर घोष लाल सलाम!

भोपाल (म.प्र.) में कॉ. भवानी शंकर घोष स्मृति सभा में श्रद्धांजलि देते हुए केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. शंकर साहा

अमृतसर में रेल दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉ. सत्यवान और पार्टी की पंजाब राज्य इकाई के प्रभारी कॉ. अमिंदरपाल सिंह ने 20 अक्तबूर 2018 को प्रैस को जारी संयुक्त वक्तव्य में अमृतसर में रेल दुर्घटना में हुई 61 लोगों की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया और मृतकों के शोक-संतप्त परिवारों के प्रति तहेदिल से शोक-संवेदना व्यक्त की। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों के लिए नि:शुल्क और सर्वोत्तम उपचार की भी मांग की।

दोनों नेताओं का मानना है कि मृतकों के परिवारों को पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पांच लाख रुपए का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ा कर प्रति मृतक के परिवार को कम से कम दस लाख रुपये तक दिया जाना चाहिए। उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए इन तरीकों के अलावा और भी तौर-तरीके खोजे जा सकते हैं। आस-पास की पटरियों पर एक समय में विपरीत दिशाओं से आने वाली दो ट्रेनों ने इस दिल दहला देने वाली दर्दनाक दुर्घटना को जन्म दिया है। यदि कार्यक्रम के आयोजकों ने रावण को आग लगाने के समय पर उचित ध्यान दिया होता, तो शायद इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। उन्होंने दुर्घटना में एक नजरिये से जांच की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के तौर-तरीकों को खोजा जा सके।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-2020
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव

(पृष्ठ 2 का शेष)

ही था। उस दौरान पैदा हुआ नगदी का संकट सरकारों ने आज लगभग स्थाई कर दिया। आज भी किसान अपनी उपज को कम भाव में बेच कर भी नगद भुगतान नहीं प्राप्त कर पा रहा है। हम जानते हैं, नगद भुगतान के अभाव में सरकार की स्वयं खरीदने, ऊंचा समर्थन मूल्य देने या बोनस देने जैसी तमाम घोषणाएं बेमायने हैं क्योंकि फसल आने के साथ ही किसान के पास सबसे पहले आते हैं कर्ज के तगादे। उसे फसल आने पर सब का हिसाब करना होता है, यहाँ तक कि जिस ट्रैक्टर-ट्राली से वह मंडी तक अपनी फसल लाता है, उसका किराया भी उसे तभी चुकाना होता है। छोटे किसानों के लिए तो यह और भी ज्यादा दुखदायी है लेकिन देखा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने सोसायटी पर खरीदी के नाम पर एक नया भ्रष्ट तंत्र विकसित किया। किसानों को फसल तुलवाने में एक-एक, दो-दो माह के नंबर दिए गए। नंबर आने के बाद भी उन्हें छह-सात दिन वहीं इंतजार कराया गया। इस बार चने को तीन-तीन बार छलने से छानकर खरीदा गया। इसके बावजूद कई जगह चने का अभी भी भुगतान शेष है। इस कष्टदायी शोषण के बाद एक कदम और आगे बढ़कर अब सरकार किसानों से कह रही है कि अपनी उपज वापस ले जाओ, हम भुगतान नहीं कर पाएंगे। यह है किसानों की लूट की पराकाष्ठा। इस लूट का शिकार होते किसान लगातार बदहाल होते जा रहे हैं। कर्ज के बोझ के कारण मध्य प्रदेश में प्रतिदिन किसान आत्महत्या करते हैं ।

इसके बावजूद सरकार किसानों को राहत देने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री व भाजपा के अन्य मंत्रियों का रवैया बेहद असंवेदनशील है। किसानों की आत्महत्या पर मंत्रीगण लगातार बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। किसी मंत्री ने किसानों की आत्महत्याओं को कर्मों का फल कहकर उनका उपहास उड़ाया, तो कोई किसानों की आत्महत्याओं को प्रेम प्रसंग और किसानों को नशे के आदी होना बताता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या को भूत-प्रेत का साया बताकर किसानों को मजाक बनाया गया। यही है शोषित-पीड़ित किसानों के प्रति मध्य प्रदेश सरकार का रवैया।

इन सबके साथ भूमि अधिग्रहण संबंधी भाजपा-कांग्रेस का रवैया किसानों को भूलना नहीं चाहिए। सत्ता में आते ही मोदी सरकार द्वारा घोर किसान-विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2015 लाया गया था जिसे किसानों की व्यापक एकता द्वारा हुये विरोध के कारण वापस लेना पड़ा था। लेकिन किसानों को यह याद रखना है कि भाजपा-नीत केंद्र व राज्य सरकारों ने अपनी पूंजीपतियों के प्रति इस मंशा को त्यागा नहीं है। मार्च 2017 में शिवराज सरकार ने स्पष्ट बयान दिया था कि ग्रीन बेल्ट या सड़क निर्माण के अधीन आने वाली जमीनों पर बगैर किसी मुआवजे के अधिग्रहण संभव होगा।(24 मार्च नई दुनिया 2017)

यह वही कांग्रेस-भाजपा हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गोली मारी है। 12 जनवरी 1998 में कांग्रेस सरकार के दौरान मुलताई में 24 आंदोलनकारी किसानों को पुलिस द्वारा गोली मार दी गई थी। इतिहास फिर 2017 में भाजपा सरकार द्वारा दोहराया गया 6 जून 2017 को अपनी जायज मांगों को लेकर मंदसौर में प्रदर्शन कर रहे 6 किसानों को सीने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपने मालिक पूंजीपति वर्ग के प्रति वफादारी निभाना ही इन पार्टियों का चरित्र है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के निजीकरण ने बढ़ायी लोगों की परेशानियां

1991 उदारीकरण-भूमंडलीकरण की नीति के बाद दुनियाभर में गहन आर्थिक संकट से उभरने के लिए तमाम पूंजीवादी देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राशन, परिवहन, बीमा आदि सेवा क्षेत्रों में व्यापार के लिये खोला गया। जबकि पहले इन क्षेत्रों में व्यापार की मनाही थी। तब से लेकर आज तक विभिन्न सरकारें इसी एजेंडे को लेकर काम कर रहीं हैं। मध्य प्रदेश भी निजीकरण करने के मामले में पीछे नहीं है। अभी हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को एक निजी हाथों में सौंप दिया गया, जहाँ पार्किंग शुल्क ही आम आदमी की क्षमता से बाहर है। आज आम जनता इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रही है।

शिक्षा

भाजपा की शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग को बंद करने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश के 1 लाख 20 हजार सरकारी स्कूलों में से 1 लाख 8 हजार सरकारी स्कूलों को सरकार 'क्लोजर व मर्जर', 'एक परिसर एक शाला' के नाम पर बंद करने की योजना बना चुकी है। पिछले दिनों खबर आई कि सरकार सभी विद्यालयों का संचालन निजी हाथों में देने की तैयारी में हैं। जबकि प्रदेश में लगभग 60,000 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। 5000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षा बजट को लगातार घटाया जा रहा है। शिक्षकों की पर्याप्त स्थाई भर्ती न करके शिक्षा की मूलभूत संरचना को ध्वस्त किया जा रहा है।

शिक्षा अधिकार अधिनियम के बाद से ही पूरे देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी कक्षा एक से आठवी तक सभी को बेरोकटोक पास करने की नीति को लागू किया गया एंव पांचवीं-आठवी कक्षा को बोर्ड से हटा दिया गया। इन नीतियों के बदलाव के दुष्परिणाम शीघ्र ही सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सीखने का स्तर भारत में सबसे बदतर है। वर्ष 2014 शिक्षा रिपोर्ट (एएसईआर) की वार्षिक स्थिति के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में सर्वेक्षण किए गए बच्चों में से कक्षा पांच के केवल 34 फीसदी छात्र ही दूसरी कक्षा की किताबें ठीक से पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा पांच के केवल 31 फीसदी छात्र हैं, जो गणित में घटाव कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप लचर हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का दोषारोपण शिक्षकों के सर पर मढ़ा जा रहा है। शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है।

शिक्षा जो किसी राष्ट्र की नींव मानी जाती है, जिसके माध्यम से नागरिकों का चरित्र निर्माण होता है। शिक्षा से ही इंसानी विवेक तैयार होता है जो सही और गलत में विभेद कर अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए समाज विकास में अपना योगदान देता है। लेकिन केंद्र व राज्य सरकार पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने पर आमादा है। शिक्षा के क्षेत्र में शासक वर्ग दोतरफा हमला कर रहा है, एक तरफ तो शिक्षा के सांप्रदायिकीकरण इतिहास व विज्ञान के साथ छेड़छाड़ करके शिक्षा के सार तत्व को ही खत्म करते हुए छात्र-नौजवानों को तर्कविहीन कर देना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा का निजीकरण-व्यापारीकरण करने के माध्यम से लाखों लाख बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास कर रहा है।

स्वास्थ्य

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 11082 लोगों पर महज एक डॉक्टर है। वहीं मध्य प्रदेश की स्थिति और भी खराब है। यहां लगभग 25000 लोगों के बीच एक डॉक्टर है। मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसमें भी विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव है। निमोनिया से मरने वाले बच्चों के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है, जहां हर साल 1 लाख 221 बच्चे पांच साल की आयु पूरी नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश में आज स्वास्थ्य की स्थिति देखते हैं तो जहां एक ओर स्वास्थ्य के आंकड़े चीख-चीखकर प्रदेश की कहानी बयां कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार की थोथी घोषणाओं की पोल खोल रहे हैं। शिशु मृत्यु दर के मामले में प्रदेश सरकार पहले स्थान पर है, तो मातृ-मृत्यु दर के मामले में दूसरे स्थान पर है। प्रतिदिन प्रदेश में 371 शिशु एंव 35 महिलाएं प्रसव के दौरान या प्रसव में आई जटिलताओं के कारण दम तोड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 96 हजार से ज्यादा शिशुओं ने अपनी जान गवाई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2016 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पर 47 शिशुओ की मौत हो जाती है।(नई दुनिया 13 जनवरी 2018)

ये आंकड़े सरकार की जननी सुरक्षा जैसी तमाम योजनाओं का भंडाफोड़ कर देते हैं। एक ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगातार स्वास्थ्य का निजीकरण करना जनता पर तीव्र हमला है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत अलीराजपुर जिले के जिला अस्पताल को पीपीपी मॉडल के तहत एक निजी कंपनी को सौंपकर की जा चुकी है।

बीमारी भले ही आम लोगों के लिए तकलीफदेह हो, परंतु कॉरपोरेट घरानों के लिए तो यह हर्षोल्लास का विषय है। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के चलते आज बीमारी और मरीज ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के साधन में तब्दील हो गए हैं। चिकित्सीय नैतिकता को ताक पर रखकर किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसकी दुख-तकलीफों पर खड़ा यह लूट का बाजार आज लाखों लोगों को कंगाल कर रहा है। वहीं हजारों लोगों की जानें भी ले रहा है। कई जीवन-रक्षक दवाओं को पिछले 2 वर्षों में दोगुना तक महंगा कर दिया गया है। बड़ी-बड़ी कंपनियों को आखिर यह मौका किसने दिया? जनता की कहलाने वाली इन्ही सत्तासीन पार्टियों ने दिया। अब गांव, नगर, महानगर स्तर पर शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं को ठप्प कर उनको प्रायवेट हाथो में देने की तैयारी है।

हमारे देश में कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है जो कि पड़ोसी देश मालदीव, भूटान, श्रीलंका, नेपाल से भी कम है। सरकार शासकीय अस्पतालों की दशा सुधारने की बजाय स्वास्थ्य बीमा का झांसा देकर निजी अस्पतालों को फायदा पंहुचाने की नीति लाई है। प्रदेश के कई शासकीय अस्पतालों में आपातकाल से निपटने का कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में थोड़ा भी जटिल केस आ जाए, तो उसके उपचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। आज लाखों लाख महिलाएं अपने गांव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं।

पेयजल

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए पानी का निजीकरण कर रही है। 2015 में इसकी शुरुआत खंडवा जिले से की गई, जहां विश्वा नामक कंपनी नर्मदा से पानी लाकर पेयजल उपलब्ध कराने का काम करेगी। पीपीपी मॉडल के तहत सरकार ने स्वयं 106 करोड़ रुपये इस कम्पनी को दिये, पर इसके बाबजूद लोगों को साफ पानी मुहैया कराने में कम्पनी असफल रही। वहीं आम आदमी के लिए पानी का खर्च बढ़ गया है। जहां पर लोग जल कर के रूप में 50 रुपये देते थे, वहां अब 200 रुपये तक देने पड़ते हैं। कई महानगरों में पानी के लिए मीटर लगा दिए गए हैं।

बड़े महानगरों से लेकर छोटे-छोटे कस्बों में तक में पेयजल को जानबूझकर दूषित कर इसके व्यवसाय को चमकाया जा रहा है। पुरानी पाइप लाइनों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। सही वाटर फिल्टर व साफ-सफाई और देखरेख के अभाव में शासकीय जल वितरण द्वारा प्रदाय जल को दूषित देखकर जनता आज कई घरों में मिनरल वाटर खरीदने पर विवश हैं। पीपीपी माडल के नाम पर सरकार पानी का निजीकरण करना चाहती है।

बिजली

मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों की मनमानी, आंकलित खपत, औसत खपत के नाम पर बिजली बिलों में धांधली, अनियमितताएं एवं गैर-जिम्मेदारी पूर्ण रवैया जग जाहिर है। आज हर आदमी असहनीय बिजली बिलों को देख कर परेशान हैं और बिजली बिल चुका पाना धीरे-धीरे उसकी क्षमता से बाहर हो रहा है। मध्य प्रदेश में बिजली के निजीकरण की शुरुआत पिछली कांग्रेस सरकार के जमाने से ही हो चुकी थी। उसके बाद विद्युत अधिनियम 2003 के बाद इस दिशा में भाजपा सरकार ने भी निजीकरण की नीति को और तेजी से आगे बढ़ाया। यहां 2003 में 1 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली दर थी जो आज बढ़ते-बढ़ते 6 रुपये प्रति यूनिट तक हो गई। पिछले वर्ष 2017 में घरेलू बिजली दरें 7.8% तक बढ़ाई गईं। अगर आप 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बिल 1325 तक आ सकता है। बिजली दरों में वृद्धि लगातार जारी है। लेकिन इसके अलावा बिजली मीटरों में गड़बड़ी, बिलों में धांधली, कनेक्शन लेने व कनेक्शन सुधरवाने, मीटर बदलवाने जैसी समस्याओं का लोग रोज सामना कर रहे हैं।

देहात में बिजली की हालत और भी बदतर है। आज कई गांव बिल न चुका पाने के कारण अंधेरे में डूबे हुए हैं। वहीं खेती-किसानी के लिए आवश्यक बिजली के लिए किसानों को स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर बिजली के खंभे, तार आदि खरीदने पड़ रहे हैं। साथ ही किसानों को निजी तौर पर ट्रांसफार्मर तक रखवाना पड़ता है। प्रतिवर्ष स्थाई और अस्थाई कनेक्शन की राशि में लगातार वृद्धि की जा रही है। वहीं सिंचाई के समय किसान बिजली कंपनी के भ्रष्टाचार का भी शिकार होता है।

आम जनता की परवाह किए बगैर मोदी सरकार एक कदम आगे बढ़कर पहले से ही जनविरोधी बिजली एक्ट 2003 में संशोधन कर उसे और भी कठोर व कंपनियों के लिए लाभदायी बनाना चाहती है। 1 अक्टूबर 2018 को हिंदुस्तान समाचार में छपी खबर के अनुसार बिजली कंपनियों के कानून में यह बदलाव देश के लिए खतरनाक साबित होगा। सरकार इसके माध्यम से घरेलू, किसान, व्यवसाय, उद्योग सभी के लिये एक सा टैरिफ लाने का प्रावधान ला रही है। यदि उपभोक्ता की कोई चूक होती है, तो उसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ तक कि ऐसे केसों में सुनवाई साधारण कोर्ट में न होकर कंपनी द्वारा स्थापित ट्रिब्यूनल में होगी। जहाँ अपने आप को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की बताई गई

(शेष पृष्ठ 7 पर)

आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव

(पृष्ठ 6 का शेष)

है। इसी तरह सब्सिडी खत्म करने सहित अब बिजली के दाम पेट्रोल-डीजल के दामों की तरह प्रतिदिन अपने मन मुताबिक बढ़ाए जाने का प्रावधान भी शामिल है क्योंकि सरकार बिजली को भी नियंत्रण मुक्त करना चाहती है।

जबकि देखा जाए, तो आजादी के बाद आम जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई से विद्युत व्यवस्था का निर्माण किया गया था। विद्युत का फैलाव इतने बड़े विशाल देश में काफी हद तक किया गया था। इसके लिए खर्च का भुगतान आम जनता ने विभिन्न टैक्सों की अदायगी के माध्यम से किया था। जिस विद्युत मंडल की स्वामी जनता थी, आज विद्युत का निजीकरण करके व कंपनियों के मनमाने रवैये के कारण कंपनी खुद इसकी मालिक बन बैठी है। आम जनता को चोर बताया जाता है। समय पर बिल भुगतान नहीं होने की स्थिति में किसानों, मजदूरों व आम लोगों के सामान की खुलेआम नीलामी तक कर दी जाती है।

भ्रष्टाचार में भी नम्बर वन शिवराज सरकार

यूँ तो मध्य प्रदेश में अनेक शिक्षण संस्थानों व अस्पतालों में माननीय मुख्यमंत्री पर भाजपा कांग्रेस विधायकों की हिस्सेदारी है। अगर इससे आगे बढ़ते हुए बात घपले-घोटालों की करें, तो पिछले 12 वर्षों में 156 प्रमुख घोटालों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। डम्पर घोटाला, सुगनीदेवी जमीन घोटाला, अवैध रेत उत्खनन व सिंहस्थ आदि भ्रष्टाचार के बड़े घोटाले सामने आये हैं। घोटालों की फेहरिस्त में सबसे बड़ा है व्यापम घोटाला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस घोटाले से गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के लगभग 1 करोड़ 16 लाख होनहार बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया और नेताओं (पक्ष व विपक्ष) कई अधिकारियों की अयोग्य संतानों को पैसे के दम से परीक्षा पास कराई गई।

हैरत की बात तो यह है, इस घोटाले से जुड़े लगभग 50 लोगों की जांच के दौरान कथित तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी।

बहरहाल मामला सीबीआई के पास है,लेकिन सवाल यह है कि उन मेहनती योग्य लाखों छात्रों का क्या होगा जो इस घोटाले के कारण अपने जीवन के सुनहरे काल को दांव पर लगा चुके हैं? क्या उनका वह समय लौटाया जा सकता है? हजारों छात्रों ने अपने परिवार की संचित निधि से, तो किसी ने अपनी जमीन गिरवी रख कर पढ़ाई की होगी,क्या कोई नेता दे सकता है इसका खामियाजा? नहीं। लेकिन इनके खिलाफ तीव्र प्रतिवाद दर्ज कराना सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करना आज समय की मांग है।

एक तरफ शिवराज सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर गांव-गांव घूमकर नर्मदा यात्रा करती है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांवों के लगभग 40 हजार परिवारों को बगैर किसी उचित मुआवजा और पुनर्वास के अपना घर-द्वार छोड़कर पलायन करने पर मजबूर करती है। डूब प्रभावित ये 40 हजार परिवार जिसमें हजारों छोटे-छोटे बच्चे महिलाएं शामिल हैं, क्या ये हमारे देश के नागरिक नहीं हैं? क्या पहले इनका संतुष्टिजनक पुनर्वास नहीं करना चाहिए था? लेकिन पुनर्वास के नाम पर बगैर किसी बुनियादी सुविधाओं के टीन शेड के छोटे-छोटे कमरों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी भाजपा सरकार के राज में मंत्री से लेकर संतरी तक, सब बेलगाम होकर आम लोगों का शोषण कर रहे हैं।

महिलाओं व बच्चियों पर लगातार बढ़ते दिल दहला देने वाले अपराध

26 जून 2018 को वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वे में भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बताया गया है। संस्कृति की दुहाई देने वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की उदासीनता के चलते महिलाओं व बच्चियों पर होने वाले अपराधों के मामले में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है। यहां हर दिन 14 दुष्कर्म, 28 छेड़छाड़ और 156 महिलाओं के साथ किसी न किसी तरह की प्रताड़ना होती है। जून 2017 से जून 2018 के बीच, मध्य प्रदेश में 59,930 महिलाएं दुष्कर्म, अपहरण व प्रताड़ना की शिकार हुई हैं। संस्कृति के तथाकथित रक्षक अपने बड़बोले वचनों में महिलाओं को नसीहत दे रहे हैं कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए। रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। जींस नहीं पहनना चाहिए। लेकिन इस तरह की दकियानूसी सोच से सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। यह सच है कि महिला हो या पुरुष सभी को ही शालीन कपड़े पहनने चाहिए। पर आज देखा जा रहा है कि 2 माह की बच्चियों से लेकर 80 साल की वृद्ध महिला तक के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आ रही हैं। अगस्त 2018 में इंदौर में एक 8 माह की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इससे पहले 20 अप्रैल 2018 को फुटपाथ पर सो रही 4 महीने की बच्ची को चुपचाप उठा कर उस मासूम के साथ बलात्कार किया गया और उसका सिर पटक-पटक कर उसकी हत्या कर दी गई। उस बच्ची का परिवार राजबाड़े पर गुब्बारे बेचकर किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। देशभर में महिलाओं और बच्चियों के प्रति यौन हिंसा ही नहीं, बल्कि कहा जाए कि दरिंदगी का युद्ध छेड़ रखा है। भोपाल, होशंगाबाद के मुक-बधिर आश्रम की घटनाएं मानवता को शर्मसार कर देने वाली हैं। इन आश्रमों में पल रही मूक-बधिर बच्चियों का कई वर्षों से संचालकों द्वारा यौन शोषण किया जा रहा था। उन्होंने डरते-डरते इसका खुलासा किया। जरा सोच कर देखिए जो बच्चे बेजुबान हैं, उन्हें तो और भी ज्यादा प्यार स्नेह की जरूरत थी। पर हैवानियत की तमाम सीमाएं लांघते हुए इन आश्रमों के संचालकों द्वारा उन्हें वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी तरह ग्वालियर में स्नेहालय नामक संस्था में रह रहे अनाथ बच्चों के यौन शोषण की घटना सामने आई हैं। बच्चे अनाथ हैं, ऐसा कोई उनका नहीं है जो विरोध दर्ज करा सके, शायद यही सोच कर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यह कितना कुत्सित विचार है!

अगर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर नजर डालें, तो आप भय और आतंक से सिहर उठेंगे। हमारे देश में वर्ष 2001 से 2016 के बीच बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों में 1705 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन 16 सालों में बच्चों के प्रति यौन अपराधों के कुल 1,53,701 मामले दर्ज किए गए। उनमें अकेले मध्य प्रदेश में ही 30,659 मामले दर्ज हुए और हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश इस मामले में भी प्रथम स्थान पर है। जरा सोचिए आखिर कैसे समाज में हम रह रहे हैं? एक ऐसा समाज जो महिला और बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सकता।

यह सवाल है उन लोगों से जो पिछले 15 वर्षों से प्रदेश में राज कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। क्या संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए 15 वर्ष काफी नहीं थे! लेकिन एक सोची-समझी साजिश के तहत युवाओं को नशाखोरी व अश्लीलता में डुबाया जा रहा है।

वर्ष 2016 में एनसीआरबी की रिपोर्ट और स्वयं अल्कोहल एवं ड्रग इनफॉरमेशन सेंटर ऑफ इंडिया ने बताया कि शराबखोरी के कारण लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, विशेषकर महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ रही यौन हिंसा के लिए शराब, नशा और गंदी फिल्में, पोर्न साइट्स जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 69% अपराध, 40% सड़क हादसे, 80% तलाक व अन्य महिला उत्पीड़न के मामलों के लिए ड्रग और शराब का नशा जिम्मेदार है। भोपाल, ग्वालियर, सागर सहित प्रदेश के लगभग सभी शहरों में महिलाओं ने घरों से निकल कर शराब बंदी की मांग उठाई, कई जगह महिलाओं ने शराब के ठेकों के आगे बैठकर कई दिनों तक धरना दिया। कहीं-कहीं आक्रोशित भीड़ ने शराब के ठेकों को आग लगा दी। इतने विरोध के बावजूद भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में शराब के कारोबार को और भी बढ़ा रही है। शराब के नए-नए ठेके खोले जा रहे हैं। शराब की खपत बढ़ाने के लिए उसे सस्ता किया जा रहा है। शराब दुकान खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। आज भी रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके संचालित किये जा रहे हैं। आज गांव-देहात में बच्चे शराब स्मेक जैसे नशे के आदी हो कर अपने घर परिवार की संपत्ति बेच रहे हैं। अखबार ने बताया कि आधे से ज्यादा शराब कारोबारी भाजपा-कांग्रेस से जुड़े लोग ही हैं। यही नेता लोग चुनावों में युवा बेरोजगारों को व्यापक पैमाने पर शराब नशे के आदी बनाते हैं। बस्तियों में जाकर शराब बांटते हैं। चुनावों के दौरान लाखों नए लोग शराबियों में शामिल हो जाते हैं।

वहीं दूसरी तरफ अश्लीलता को फैलाया जा रहा है। पत्र-पत्रिकाओं, टीवी, इंटरनेट के माध्यम से गंदी फिल्में, गंदे पोस्टरों और पोर्न वेबसाइटों का युवाओं के बीच तेजी से प्रचार किया जा रहा है। फैशन शो, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सिर्फ सामग्री के रूप में दिखाया जा रहा है। छोटे-छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। अश्लीलता-नशाखोरी इंसान के विवेक को मारने का काम करती हैं। वे इन्सान में बुरी प्रवृत्तियों को पनपाती हैं। तब हमें समझना होगा कि जो युवक समाज निर्माण में अपना योगदान दे सकता था, वह अश्लीलता, अप-संस्कृति व नशाखोरी में डूबकर महिलाओं व बच्चियों पर अपराध को अंजाम दे रहा है। इस तरह के अधिकांश मामलों में अपराधी द्वारा किया गया अपराध नशे की हालत में किया गया होता है। वहीं बहुत से अपराधी पोर्न फिल्मों के आदी पाए गए। तब सवाल यह है कि आखिर समाज से शराबखोरी, नशाखोरी व अश्लीलता को बंद क्यों नहीं किया जाता? सरकारी तर्क है कि शराबबंदी से राजस्व का नुकसान होगा। पर सरकार का यह सरासर झूठा तर्क है। क्या राजस्व बढ़ाने के लिए लाखों महिलाओं और बच्चियों की बलि दी जाएगी? उनकी जान और अस्मत से खिलवाड़ किया जाएगा? वैसे भी केंद्र और राज्य सरकारें जीएसटी, पैट्रोल, डीजल व तमाम वस्तुओं और सेवाओं से टैक्स वसूल रही हैं। इन्हें कौन सा जनता के हित में इस्तेमाल किया जाता है।

दरअसल शराबखोरी अश्लीलता, नशाखोरी को शासक द्वारा जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश के नौजवान आम नागरिकों की नैतिक रीढ़ पर प्रहार किया जा सके और वे अन्याय-अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के काबिल नहीं बन सकें। इंसान के विवेक को मजबूत कर उसके चरित्र निर्माण में सहायक शिक्षा को महंगा व अतार्किक बनाते हुए बुरी प्रवृत्तियों को उकसाने वाले नशे और अश्लीलता को बढ़ावा देना सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये सत्ता की भूखी चुनावी पार्टियाँ कितनी देशभक्त और कितनी जन-हितैषी हैं।

साम्प्रदायिकता-जातिवाद, उग्र राष्ट्रवाद की आड़ में जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास

जहाँ मध्य प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं व बच्चों पर अपराध एवं आम जनता की तकलीफें बढ़ रही हैं, वहीं पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में भाजपा व इसके अनुसांगिक संगठन सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद को फैलाकर मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे-जैसे आम जनता पर सरकार की नीतियों के हमले तेज हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा धर्म, जाति, गौरक्षा, लव जिहाद जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाया जा रहा है।

सभी चुनावी पार्टियां द्वारा चुनावों में धार्मिक और जातिगत भावनाएं भड़का कर जातीय समीकरण बैठा कर वोट बटोरे जाते हैं। अखंड भारत की बात करने वाली भाजपा सरकार इस मामले में एक कदम आगे है, इसने देश को आज कई हिस्सों में विभाजित कर दिया है। इसने हिंदू-मुस्लिम, सवर्ण-दलित, भाषा व क्षेत्र के नाम पर विभाजन की खाई को गहरा किया है, जिसे पाटना और भी मुश्किल होता जा रहा है। उग्र राष्ट्रवाद की आड़ में ये दलितों, अल्पसंख्यकों और प्रगतिशील विचारों पर खुलेआम हमले कर रहे हैं। गौहत्या, लव जिहाद जैसी झूठी अफवाहें फैलाकर और लोगों की भावनाएं भड़का कर बेकसूर लोगों से मार-पीट करने, यहाँ तक की भीड़ द्वारा उनको पीट-पीटकर हत्या कर देने की जघन्य घटनाएं भी घटित हो रही हैं। इन्हीं भावनाओं के चलते देश में प्रगतिशील विचारक एम.एम. कुलबर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पांसरे, गौरी लंकेश जैसे लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

क्रांतिकारी राजनीति को मजबूत करें, जन जीवन की ज्वलंत समस्याओं पर आंदोलन संगठित करने हेतु एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) का साथ दें

इस तरह समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी पतन होते देखकर प्रत्येक ईमानदार प्रगतिशील नागरिक समाज को लेकर गहरी व्यथा-वेदना के साथ चिंतित है। जहां एक तरफ आज आम लोगों पर आर्थिक हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंसान की नीति-नैतिकता पर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है, उसे अतार्किक व रूढ़िवादी बनाकर उसके अंदर रची-बसी कोमल भावनाओं, संवेदनाओं व इंसानियत को खत्म करने की साजिश हो रही है। राजनीति के स्तर में इस घोर गिरावट को देखकर आम लोगों के मन में राजनीति के प्रति नफरत का भाव पैदा हो रहा है। आखिर आजादी के 71 वर्षों बाद भी देश के ऐसे हालात क्यों हैं?

इस सवाल पर चर्चा करते हुए इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतनकार कामरेड शिवदास घोष ने हमें सिखाया कि हमारा समाज एक वर्ग-विभाजित समाज है। एक तरफ हैं चंद पूंजीपति और दूसरी तरफ हैं सर्वहारा, मजदूर, किसान और शोषित-पीड़ित आम लोग। वर्ग-विभाजित समाज में राजनीति भी वर्ग से परे नहीं हो सकती है, वह या तो चंद पूंजीपतियों की भरोसेमंद पार्टियों के माध्यम से पूंजीपति वर्ग की राजनीति होगी या असंख्य मेहनतकश, गरीब, मजदूर किसान, आम जनता की राजनीति होगी। कोई एक पार्टी या तो पूंजीपति वर्ग की सेवा करेगी या मेहनतकश वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण करेगी।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 of every month, Fortnightly, Date of Publication : November 5, 2018

आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव

(पृष्ठ 7 का शेष)

देश की वर्तमान हालत को देखकर हम सहज समझ सकते हैं कि आज सत्ता पर यही पूंजीपति वर्ग काबिज है। उत्पादन के तमाम साधनों पर कब्जा कर यह अकूत मुनाफा लूटा जा रहा है। आजादी के बाद गरीबी अमीरी की खाई निरंतर बढ़ी है। इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ऑक्सफैम के अनुसार भारत की कुल संपत्ति के 73% हिस्से पर देश के 1% अमीरों का कब्जा है। वहीं अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार देश की 77% आबादी यानी 83 करोड़ लोग प्रतिदिन 20 रुपये से भी कम पर अपनी गुजर-बसर करने पर मजबूर हैं। यानी देश के अमीर और अमीर होते जा रहे हैं एवं गरीब और गरीब।

दरअसल दुनियाभर में व्यापक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए भारत में भी पूंजीपति वर्ग अपने विश्वस्त राजनीतिक दलों के माध्यम से उत्पादन के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसका सारा बोझ आम जनता पर डालकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन आदि सेवा क्षेत्रों में भी मुनाफा कमाने के लिए पूंजीनिवेश कर रहे हैं।

पूंजीपति वर्ग के स्वार्थ में तमाम पार्टियां कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों सहित विभिन्न राज्यों में सत्तासीन रही सपा, बसपा, यहां तक कि अपने आप को वामपंथी कहने वाली सीपीआई, सीपीआई(एम) ने भी पूंजीपतिपरस्त नीतियों का ही अनुसरण कर आम जनता को भूख, गरीबी, भुखमरी में धकेला है।

इस तरह के बुर्जुआ अवसरवाद और सोशल डेमोक्रेटिक विश्वासघात के खिलाफ, हमारी पार्टी, एसयूसीआई (सी) अकेले ही क्रांतिकारी मूल राजनीतिक लाइन का अनुसरण कर रही है और मेहनतकशों के विभिन्न तबकों को शामिल करने और पूंजीवादी दमन-उत्पीड़न और धोखे के खिलाफ मजबूती से आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक रूप से जागरूक करने की कोशिश करते हुए वर्ग संघर्षों और जन आन्दोलनों को लगातार गठित कर रही है। लेकिन हमारी पार्टी एकजुट संघर्ष को मजबूत करने के लिए और एक अवसरवादी चुनावी गठबंधन बनाने की बजाय अन्य वामपंथी दलों को लामबंद करने का भी प्रयास कर रही है। व्यापम घोटाले के खिलाफ बंद व अन्य वाम दलों के साथ संयुक्त आंदोलन गठित करने के अलावा विरोध की आवाज को दबाने वाले फासीवादी कदम के तौर पर भाजपा सरकार के द्वारा राज्य में धारा 144 को लागू करने के खिलाफ अन्य वाम दलों के साथ मिल कर बंद का आह्वान करने सहित जोरदार विरोध प्रदर्शन किए गए। शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के आंदोलनों को कुचलने में सरकार की ज्यादतियों या सरकारी स्कूल बंद करने का हमारी पार्टी ने विरोध किया।

सरदार सरोवर बांध से विस्थापितों के पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन का समर्थन करने में और मंदसौर में किसानों की हत्या के खिलाफ राज्यव्यापी बंद सहित विरोध प्रदर्शन करने में हमारा किसान संगठन एआईकेकेएमएस सबसे आगे था। हमारी पार्टी और एआईकेकेएमएस ने किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की मांग के लिए भी संघर्ष किए। पार्टी ने बिजली वितरण के निजीकरण और बीपीएल लोगों को बिजली के बिल भेजने के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। आंदोलन के दबाव में, सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा और अंततः सभी झूठे मुकदमों और फर्जी बिलों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा।

राज्य में ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) ने पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की है और महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ लगातार संघर्षरत है। एआईएमएसएस, एआईडीवाईओ और एआईडीएसओ ने संयुक्त रूप से 'शराबबंदी यात्रा' राज्य में आयोजित की, जिसमें 16 जिलों को कवर किया गया। भारी जनसमर्थन के साथ आंदोलन ने अन्यथा टस से मस न होने वाले मुख्यमंत्री को राज्य में सभी शराब की दुकानों को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध किया। फीस वृद्धि, शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण-सांप्रदायीकरण की शिक्षा-विरोधी नीतियों, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता, शैक्षिक संस्थानों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एआईडीएसओ नियमित रूप से आंदोलन गठित करता रहता है। 2008-09 में शिक्षा के आंतरिक सारतत्व को नष्ट करने के लिए राज्य में चालू की गई सेमेस्टर प्रणाली का छात्रों व शिक्षकों द्वारा विरोध किया गया। एआईडीएसओ ने विरोध की इस आवाज को बुलंद करने और राज्य के सभी 7 विश्वविद्यालयों को कवर करते हुऐ राज्यव्यापी 'सेमेस्टर हटाओ यात्रा' में समापन हुए 8 वर्षीय एंटी-सेमेस्टर आंदोलन का नेतृत्व करने में अग्रणी भूमिका निभाई। नतीजतन यह मुद्दा सामने लाया गया और आखिर में सरकार को स्नातक पाठ्यक्रम से सेमेस्टर सिस्टम वापस लेना पड़ा। बेरोजगारी और युवाओं की अन्य समस्याओं के खिलाफ स्थायी रोजगार और सभी सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की मांग को लेकर एआईडीवाईओ नियमित रूप से आंदोलन कर रहा है। एआईयूटीयूसी की इकाइयां विभिन्न उद्योगों में जायज मजदूर आंदोलन गठित करने में सक्रिय रही हैं। इस तरह, एसयूसीआई (सी) और इसके विभिन्न वर्ग और जनमोर्चों ने एक वास्तविक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में जनमानस में एक जगह बनाई है जो सत्ता-सुख की राजनीति नहीं करती है बल्कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद को उच्च नैतिकता-संस्कृति-नैतिकता पर आधारित समग्र जीवन दर्शन के रूप में देखती है जो उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कमर कसने के लिए आगे बढ़ाता है। इसी उद्देश्य को लेकर मेहनतकश वर्ग की पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) इस विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी कर रही है।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी 6 सीटों से चुनाव लड़ रही है। अगर आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे, तो जन आंदोलन की आवाज विधानसभा के अंदर भी गूंजेगी।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवार

भोपाल-गोविंदपुरा- कॉ. जॉली सरकार
ग्वालियर दक्षिण-- कॉ. रचना अग्रवाल
अशोकनगर. ---- कॉ. श्याम शाक्य
गुना ---------- कॉ. सीमा राय
सागर---------- कॉ. सोना कुशवाह
देवास -------- कॉ. हिमांशु श्रीवास्तव

तीसरी पार्टी कांग्रेस से पहले राज्य सम्मेलन सम्पन्न

(पृष्ठ 4 का शेष)

उत्तराखंड : एसयूसीआई (सी) केन्द्रीय कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों बिहार राज्य सचिव कॉ. अरुण कुमार सिंह और म.प्र. राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल की उपस्थिति में देहरादून में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सचिव के रूप में कॉ. मुकेश सेमवाल के साथ 6 सदस्यीय राज्य सांगठनिक कमेटी का गठन किया गया।

तेलंगाना : पार्टी का तेलंगाना राज्य सम्मेलन 17-18 अक्टूबर को खैराताबाद, हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. के. राधाकृष्ण व एआईकेकेएमएस के महासचिव कॉ. शंकर घोष, स्टाफ सदस्य कॉ. के. श्रीधर और कर्नाटक राज्य सचिव कॉ. के. उमा उपस्थित थे।

राज्य सचिव के रूप में कॉ. सीएच मुराहारी को लेकर 5 सदस्यीय नई राज्य सांगठनिक कमेटी गठित की गई।

एआईडीएसओ नेताओं ने की एसएफआई सम्मेलन में शिरकत

शिमला : हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुए स्टूडेन्टस फैडरेशन आफ इण्डिया (एसएफआई) के 16वें अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर एआईडीएसओ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉमरेड भाविक राजा और संगठन के अखिल भारतीय सचिवमण्डल सदस्य कॉमरेड प्रशांत कुमार उपस्थित थे। कॉ. भविक राजा ने शिक्षा और समाज पर हो रहे गंभीर फासीवादी हमले, वाम और जनवादी छात्र संगठनों की एकता की आवश्यकता और भावी चुनौतियों पर जोर देते हुए अपने विचार रखे।

एआईडीएसओ की ऑल इंडिया कमेटी की ओर से किताबों का एक सेट एसएफआई के अखिल भारतीय अध्यक्ष को भेंट किया गया और सम्मेलन का एक स्मृति चिन्ह एसआईएफ नेताओं ने एआईडीएसओ उपाध्यक्ष को भेंट किया।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503